FREEBIES CULTURE

Why in the News?

Recently, there was a petition filed in the Supreme Court to curb the practice of offering or distributing “irrational freebies”.

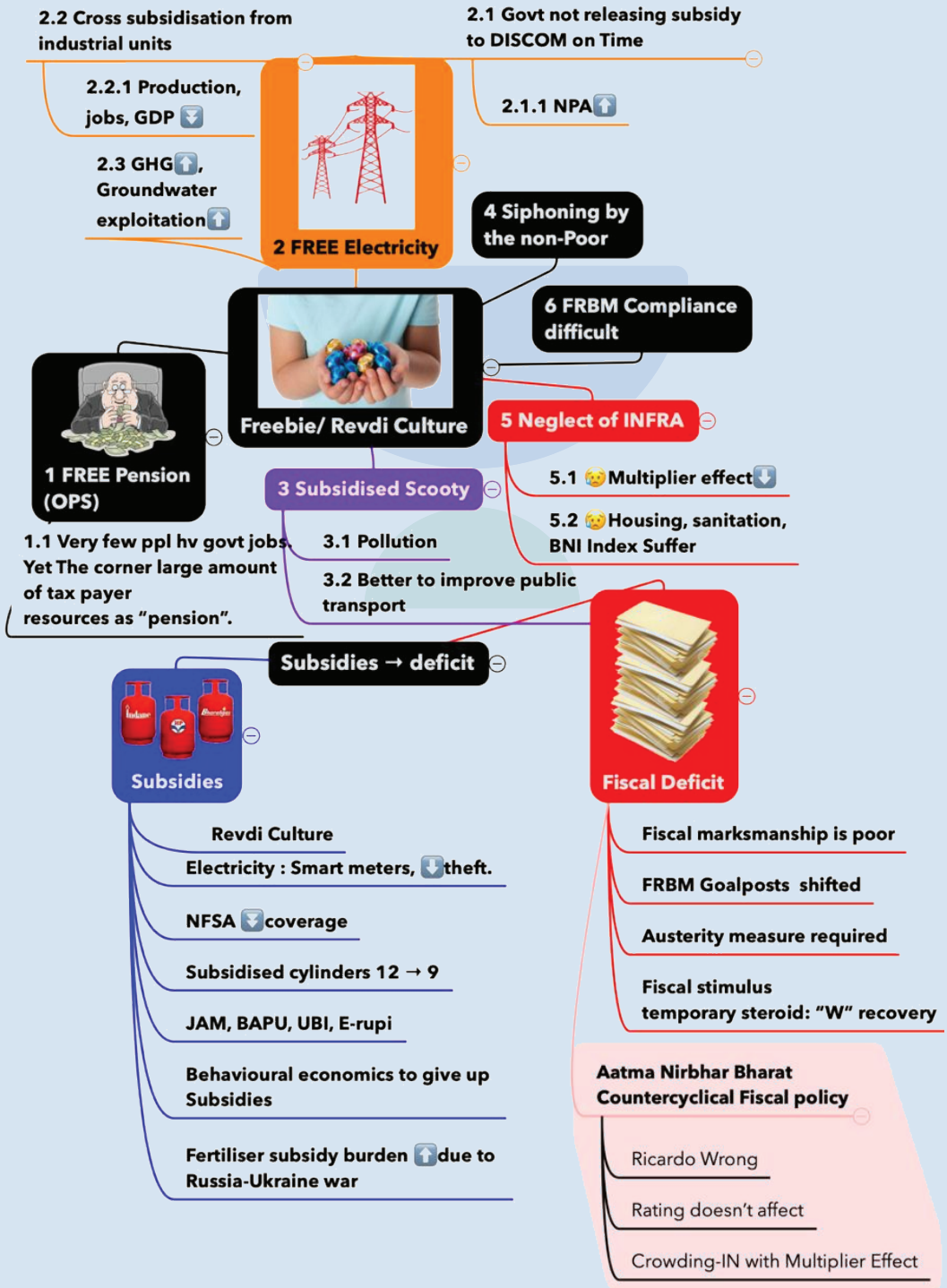

Image Source: Mrunal’s Sir Economy Handout

Views on Freebies:

- The **prime minister** has called for an end to the “revdi” culture.
- The **Reserve Bank of India**, in a report published in June, linked the precarious state of state finances to “freebies”, particularly power subsidies.
- The **Supreme Court** recommended the creation of an expert body to examine the freebies.
- **Election commission** of India also came in support of instituting a committee as suggested by the Supreme Court.

What are Freebies:

- In simple terms, it refers to a public welfare measure – any good or service – that is offered free of cost by the government to its citizens.
- But the existing legal or policy framework does not provide a precise definition for the term.

Merits of freebies

- **Facilitate growth:** It ensures basic needs like food, electricity, water etc. of the citizens, especially the underprivileged section.
- **Reduce inequality:** It addresses the concerns of marginalized sections of the society, Mitigation of income gaps; reducing inequality.
- **Lifesavers during calamity:** It can be lifesavers during a disaster or a pandemic.
- Benefits of cross-subsidisation and situation/sector-specific reliefs to address the different vulnerabilities of sections of society.

  Prevent Suicide. Ex, Farm Loan Waivers

Demerits of Freebies:

- It could be harmful for the long-term economic growth of the country.

  Place a burden on stressed fiscal resources.
- Reduces capital allocations essential for long-term growth and has a negative impact on industry.
- Impact budgetary allocations
- Misuse of resources

- Unviable pre-election promises adversely affect the informed decision-making by voters.
- Irrational freebies violates the ECI's mandate for free and fair election.
- Leaves less room for investment in Capital Infrastructure.

Measures to mitigate the negative impacts:

- There is a need to distinguish between productive and unproductive forms of welfare spending.
- Rationality is to be introduced into the disbursement of freebies and subsidies.
- The Finance Commission could be involved to look into the matter and propose solutions.
- Government can take a stand on the need to control the announcement of 'freebies' by political parties during election campaigns.
- Building public pressure towards making welfare delivery an electoral issue is the need of the hour.
- There is a need to have an institutional mechanism to control wasteful expenditure.
- The FRBM Acts need to be amended to enforce a more complete disclosure of the liabilities on their exchequers.

Conclusion:

- A debate on the merits and demerits of freebies is important.
- Any further step, such as distinguishing welfare measures from populist sops and pre-election inducements, ought to come from the legislature.

राजनीति में फ्रीबीज़ (मुफ़्त उपहार)

खबरों में क्यों?

हाल ही में, "तर्कहीन मुफ्त उपहार" देने या वितरित करने की प्रथा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

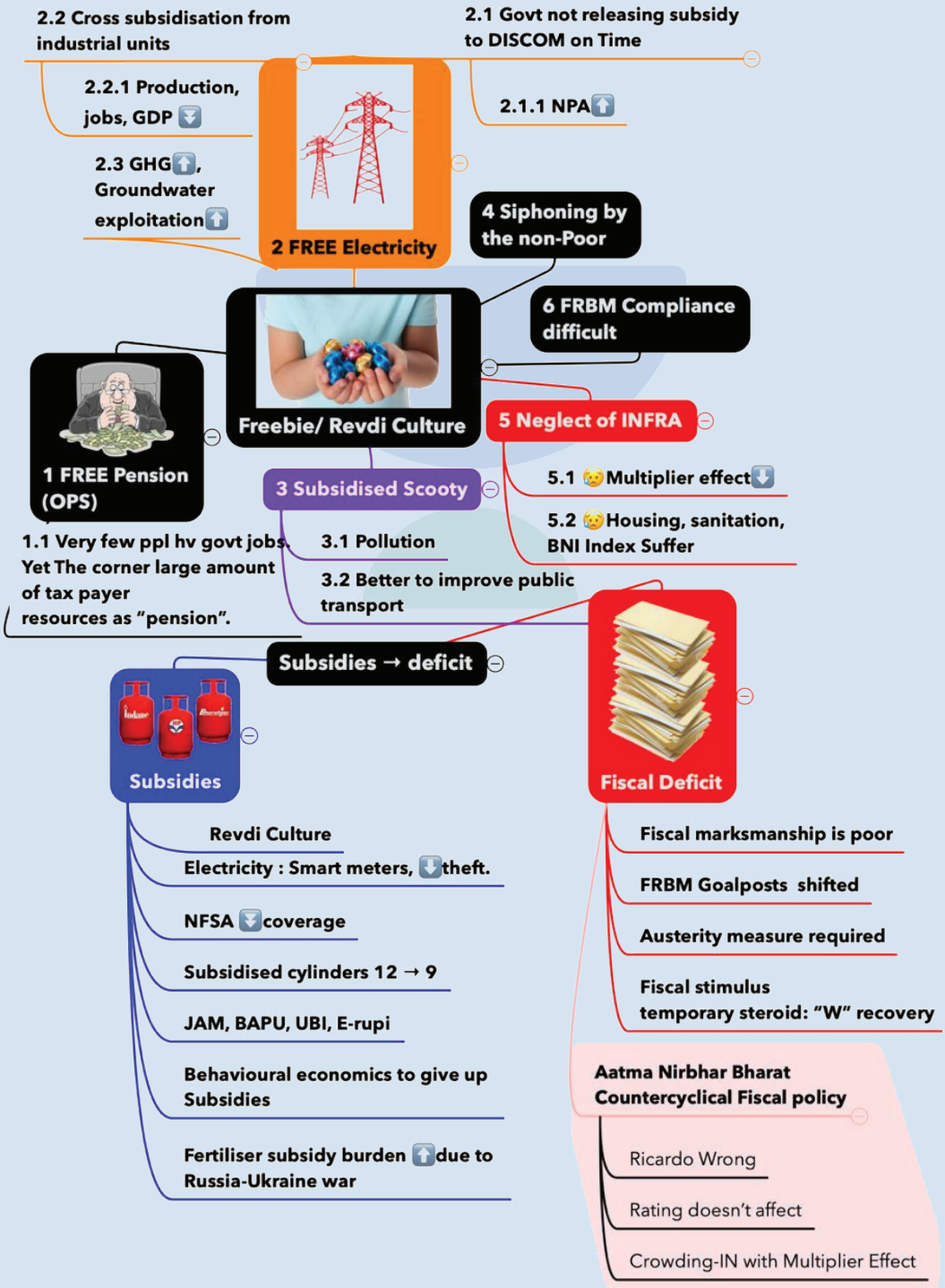

Image Source: Mrunal's Sir Economy Handout

मुफ्त उपहारों पर विचार:

- प्रधान मंत्री ने "रेवड़ी" संस्कृति को समाप्त करने का आह्वान किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में प्रकाशित एक रिपोर्ट में, राज्य के वित्त की अनिश्चित स्थिति को "मुफ्तखोरी", विशेष रूप से बिजली सब्सिडी से जोड़ा।
- सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज की जांच के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के गठन की सिफारिश की।
- भारत का चुनाव आयोग भी सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार एक समिति गठित करने के समर्थन में है।

फ्रीबीज क्या हैं:

- सरल शब्दों में, यह एक लोक कल्याणकारी उपाय को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत- कोई भी सामान या सेवा - जो सरकार द्वारा अपने नागरिकों को मुफ्त में दी जाती है।
- लेकिन मौजूदा कानूनी या नीतिगत ढांचा इस शब्द की सटीक परिभाषा प्रदान नहीं करता है।

फ्रीबीज़ के गुण

- **विकास को सुगम बनाना:** यह नागरिकों, विशेष रूप से वंचित वर्ग की भोजन, बिजली, पानी आदि जैसी बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करता है।
- **असमानता को कम करना:** यह समाज के हाशिए के वर्गों की चिंता को दूर करता है, आय अंतराल को कम करता है औरअसमानता को कम करता है।
- **आपदा के दौरान जीवन रक्षक:** आपदा या महामारी के दौरान यह जीवन रक्षक हो सकता है।
- समाज के वर्गों की विभिन्न कमजोरियों को दूर करने के लिए **क्रॉस-सब्सिडी और स्थिति/क्षेत्र-विशिष्ट** राहत के लाभ।
- आत्महत्या को रोका जा सकता है।उदाहरण के लिए, कृषि ऋण माफी

मुफ्तखोरी के दोष:

- यह देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है।
- तनावग्रस्त राजकोषीय संसाधनों पर बोझ बढ़ता है।
- दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी आवंटन को कम करता है और उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- बजटीय आवंटन को प्रभावित करता है
- संसाधनों का दुरुपयोग होता है।

- अव्यवहार्य चुनाव पूर्व वादे मतदाताओं द्वारा सूचित निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- तर्कहीन मुफ्त उपहार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के जनादेश का उल्लंघन करते हैं।
- कैपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए कम जगह छोड़ता है।

नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपाय:

- कल्याणकारी खर्च के उत्पादक और अनुत्पादक रूपों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है।
- मुफ्त उपहारों और सब्सिडी का वितरण तर्कसंगत होना चाहिए।
- इस मामले को देखने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए वित्त आयोग को शामिल किया जा सकता है।
- चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा 'मुफ्त उपहार' की घोषणा को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर सरकार एक स्टैंड ले सकती है।
- कल्याणकारी वितरण को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए जनता का दबाव बनाना समय की मांग है।
- फिजूलखर्ची को नियंत्रित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की जरूरत है।
- राजकोष पर देनदारियों का अधिक पूर्ण प्रकटीकरण लागू करने के लिए FRBM अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- मुफ्त उपहारों के गुण और दोष पर एक बहस महत्वपूर्ण है।
- विधायिका को लोकलुभावन रियायतों और चुनाव पूर्व प्रलोभनों से कल्याणकारी उपायों को अलग करना, जैसे सुधारवादी कदम उठाने चाहिए।।